के कारण उनका बहुत संतोषजक समाधान हुआ।

जहां तक Kinshasa की खबर का सवाल है, मैंने आपको बताया है कि वहां कोई गंभीर चोट नहीं आई, पता नहीं कौन सी बात कह रहे हैं, जो उन्होंने देखी, लेकिन मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि कुछ इंजरीज़ की घटना हुई, दुकानों पर पथराव भी हुआ, लेकिन कोई गंभीर चोट का मामला नहीं था। उसके बावजूद हमारे दूतावास ने उनके साथ विदेश मंत्रालय तक यह मामला उठाया और अब हमारे लोगों का वहां भी संतोषजनक समाधान हो गया है।

श्री परवेज़ हाशमीः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया है कि 20th May को दिल्ली में यह कांगो वाला incident हुआ था। 21st May को दो लोग तो पकड़े गए, लेकिन आज जब 21 July हो गई है, लेकिन अभी तक तीसरा आदमी पुलिस के हाथ नहीं आया है। यह मामला दिल्ली सरकार का है और दिल्ली से संबंधित है तथा लॉ एंड आर्डर गृह मंत्रालय के under आता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तीसरा आदमी कब तक पकड़ा जाएगा? आप उनको क्या एश्योरेंस देंगे, जब आप तीन आदमी नहीं पकड़ सकते? दो culprits आपके पास हैं, तो फिर तीसरे के बारे में तो पता होना चाहिए कि वह कहां है, यह तो वही लोग बता देंगे! आपने इस बारे में अभी तक क्या कार्रवाई की है और अभी तक वह क्यों नहीं पकड़ा गया है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः यह सच है कि तीसरा व्यक्ति अभी नहीं पकड़ा गया है और अभी दो ही व्यक्ति पकड़े गए हैं। तीसरा व्यक्ति फरार है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैंने स्वयं LG से बात की थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और अभी तीसरा व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन उन दो के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है।

Conversion of engineering colleges into skill development centres

*48. DR. KANWAR DEEP SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme is being formulated to convert existing engineering colleges into skill development centres, if so, the details thereof; and

(b) what is the status of this scheme and by when it is likely to be finalized?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) There is no proposal to convert the existing engineering colleges into skill development centres. However, a scheme has been formulated under the umbrella of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) to use the infrastructure in the engineering colleges for skilling the unemployed youth, after the college hours. All India Council for Technical Education (AICTE) implements this project and skilling is done as per the National Occupational Standards (NOS) prescribed by the Ministry

of Skill Development and Entrepreneurship. It is proposed to extend this facility to 10,000 colleges so that at least 10 lakh youth can be trained in engineering skills by March, 2019. The scheme has received enthusiastic response from the engineering colleges, with more than 1,500 engineering colleges expressing interest to participate in the programme.

DR. KANWAR DEEP SINGH: Sir, my original question was, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज बंद हो रहे हैं, उनके यहां स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट कोई प्लान बना रही है? माननीय मंत्री जी के जवाब में बताया गया है कि उन कॉलेजेज में after college hours, शाम को स्किल डेवलपमेंट की क्लासेज़ चल रही हैं। यह बहुत अच्छा प्लान है। I congratulate them. हालांकि मंत्री जी के जवाब में बताया गया है कि 10 हजार कॉलेजेज में यह कार्य करना है और अभी 1500 कॉलेजेज में यह कार्य हो चुका है। आप उसे बहुत enthusiastic मानते हैं क्योंकि यह माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत ही favourite subject है 'Skill Development' and rightfully so. मेरा कहना यह है कि thousands of engineering colleges have already applied to AICTE for closure. That is a part of my original question also. तो क्या आप कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे कि जो कॉलेजेज बंद हो रहे हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में तब्दील किया जा सके?

श्री प्रकाश जावडेकरः आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन हमारे पास जो आपका सवाल आया है, वह यह है कि whether it is a fact that a scheme is being formulated to convert existing engineering colleges into skill development centres लेकिन आपने भाव प्रकट किया कि जो कॉलेजेज बंद हो रहे हैं और जहां infrastructure है, अब बंद होने के अलग कारण हैं और हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि परसों राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हुआ, वहां भी स्किल मंत्रालय ने यह कहा है कि सभी ऐसे infrastructure जिनका स्किल डेवलपमेंट के लिए उपयोग होगा, वह उसे करना चाहते हैं। लेकिन जो existing colleges हैं, ऐसे 10 हजार कॉलेजेज हैं, उनमें से 1500 ने तुरंत response दिया है, लेकिन बाकी को भी हम 3 चीजें दे रहे हैं जोकि महत्वपूर्ण हैं। पहले तो जो existing infrastructure है, वह खत्म होने के बाद शाम को जब वह खाली रहता है, वे उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए उपयोग करें। उनके ही प्रोफेसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं और वे बाहर से भी ले सकते हैं। उसमें एचआरडी मंत्रालय 40 रुपए पर ऑवर, पर स्टूडेंट स्किल कार्यक्रम को चलाने के लिए देगा और इस तरह एक additional capacity built-up हो जाएगी। अभी हमने एक और निर्णय लिया है कि polytechnics can run ITIs. अभी हमारे देश में 12000 आईटीआईज हैं जिनमें 17 लाख स्टूडेंट्स हैं। इस तरह आईटीआईज का भी नंबर बढ़ाने की बात है। तो हम तीन तरह से कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एचआरडी भी जो existing engineering colleges हैं, उस बचे हुए समय में वे 10 लाख युवाओं को एक साल में ज्यादा अच्छी स्किल की शिक्षा दें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

DR. KANWAR DEEP SINGH: Sir, it is a very novel idea and a noble idea. I appreciate that. मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ ऑलरेडी चल रहे हैं, उन से निकले बच्चों की प्लेसमेंट कैसे हो रही है? क्या उसके लिए

सरकार की कोई प्लानिंग है? अब चूंकि आपने उसे, उस तरह से सक्षम बना दिया है, लेकिन उसके बाद उसे कोई जॉब नहीं मिली, तो क्या इसके लिए कोई विशेष योजना या कार्यक्रम है, जिसमें हम यह नोट कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिल रही है या नहीं?

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, actually यह कौशल मंत्रालय का सवाल है, लेकिन मुझे जो जानकारी है, वह मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि हर जिले के हिसाब से Skills Mapping का कार्य कुछ जिलों का हो चुका है और कुछ जिलों का हो रहा है। उस आधार पर वही स्किल सिखायी जाएगी जिसकी वहां आवश्यकता है और जो पैसा भी देने वाले हैं, वहां भी और यहां भी, उसमें प्लेसमेंट कितना होता है, वह skilling centre का performance-based evaluation है।

DR. KANWAR DEEP SINGH: Do we have a monitoring mechanism in place?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Yes.

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सर, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में भी कहा है कि यह प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस से अगर देश में स्किल डेवलपमेंट होता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने जवाब में कहा है कि आप इस योजना के तहत 10 हजार कॉलेजेज को include कर के 10 लाख लोगों को वर्ष 2019 तक involve करेंगे। यह आपने अपने जवाब के अंत में कहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1500 कॉलेजेज ने आपको response दिया है और अपना interest दिखाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन कॉलेजेज ने आपको सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया है या आज तक आपके पास कितने कॉलेजेज आए हैं, जो actually इस महत्वपूर्ण स्कीम के तहत जुड़ गए हैं और उन्होंने अपने यहां बच्चों को यह शिक्षा देनी शुरू कर दी है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें कुछ कमी है? आप इसका जवाब दें कि क्या कुछ और incentives देने की जरूरत है, उनको बढ़ाने की जरूरत है?

श्री प्रकाश जावडेकरः सभापति जी, जब शुरू में इसमें चर्चा हुई थी, तब संस्थाओं के साथ भी चर्चा हुई थी। उनके जो मुद्दे थे, उनमें एक सुझाव था कि यदि वहां प्राइवेट संस्थाएँ, दूसरे लोग आकर इनको चलाएंगे, तो जो संस्थाएँ हैं, जिनकी लेबोरेट्री है, वे कहेंगी कि हम ही करेंगी। वह बात ठीक है, and everybody is on board, तो मुझे लगता है कि इस शैक्षणिक वर्ष से, जिसकी अभी शुरूआत हो रही है, इस साल से इसको बहुत गति मिलेगी और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि इसी साल यह बड़ा मुकाम भी हासिल करेगी।

श्री राजीव शुक्लः सभापति जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि AICTE, जो एच.आर. डी. मिनिस्ट्री की संस्था है, वह उनको देखेगी और चलाएगी। मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट की राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी होती है कि वह इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए और उनको चलाए। क्या एचआरडी मिनिस्ट्री, AICTE उनका डायरेक्ट सुपरविज़न करेगी? क्योंकि "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना" के तहत यह स्कीम बहुत अच्छी है, तो क्या यह डायरेक्ट सुपरविज़न करेगी या राज्य सरकारों के जरिये इसका सुपरविज़न होगा? क्योंकि राज्य सरकारों ने यह काम प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया है। उन्होंने यह काम हर ज़ोन में, डिस्ट्रिक्ट में जगह-जगह पर एरिया बनाकर उनको दिया है। क्या आप इन 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ को डायरेक्ट सुपरवाइज़ करेंगे या यह स्टेट गवर्नमेंट्स के उसी प्रोसिज़र के थ्रू होगा, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं?

श्री प्रकाश जावडेकरः सभापति जी, ऐसा है कि प्रधान मंत्री जी ने पहली दफ़ा कौशल विकास मंत्रालय का निर्माण किया है। बाकी जगहों पर कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं और कौशल विकास के नए-नए केंद्र भी बनेंगे, लेकिन अभी उनकी मॉनिटरिंग वह मंत्रालय करता है। टोटल स्कीम की overseeing वही कर रहे हैं, लेकिन जहां तक existing 10,000 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की, कॉलेजेज़ की बात है, उनको हम अपने बजट से पैसा देंगे और उसमें जो एडीशनल मैनपावर तैयार होगी, उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे।

श्री राजीव शुक्लः किसको देंगे? Would you be giving it to the State Governments, or you would be giving it directly to those colleges?

श्री प्रकाश जावडेकरः यह AICTE करती है। कॉलेज तो वैसे भी ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Would AICTE be directly supervising these colleges?

श्री प्रकाश जावडेकरः अभी भी, जो स्कीम है, इसमें aided भी होते हैं और unaided भी होते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार जो काम करती है, वह राज्य सरकार करती रहेगी।

श्री राजीव शुक्लः ऐम क्या है इस स्कीम का? यदि आपके पास जवाब नहीं है तो आप बाद में लिखकर भिजवा दीजिएगा।

श्री प्रकाश जावडेकरः मैं आपको वही बता रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप जवाब सुन लीजिए।

श्री प्रकाश जावडेकरः इसका जो पैसा देना है, वह हम अपने बजट से देंगे। Skill Councils में राज्य सरकार की भी सहभागिता है। जो Skill Councils हैं, SDKs और NSDA, वे अप्रूव्ड स्किल कौंसिल्स उसको मॉनिटर करेंगी।

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, he did not get the question that I asked. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No supplementary on supplementaries.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, there are ambiguities in the answer. The answer hasn't come. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, he did not answer it properly. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Yechuryji, it is not your question. ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: Mr. Minister, just clarify: Is this money going to the State Governments, to the State Engineering Colleges, Government Colleges or to the private players? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: That is what he is asking.

SHRI SITARAM YECHURY: Are you making it a commercialization of skill education, or is it going to be accessible to all? That is the question. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रकाश जावडेकरः सभापति जी, मैं पहले बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो public-funded institutes हैं, वे public-funded institutes ही रहेंगे, उसमें प्राइवेट का कोई मुद्दा नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको वही बता रहा हूं कि रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ प्राइवेट सेंटर में भी हैं, deemed university के भी हैं, और अन्य अनेक लोगों के भी बहुत हैं। इसमें AICTE डायरेक्टली, वहां पर, जहां पर स्टूडेंट, पर ऑवर जो पैसा देना है, वह सेंटर्स को, यानी colleges को 30 per cent on admission, next 40 per cent on utilization, 20 per cent after completion and 20 per cent after jobs, ऐसा देने का प्रोविज़न है, इसलिए जो केंद्र जैसे चल रहे हैं, वे वैसे ही हैं। जैसे public-funded केंद्र public-funded ही है, उसमें प्राइवेटाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है।

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धेः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की समस्या unemployment से भी अधिक un-employability की है। मनुष्य शक्ति की आवश्यकता एक तरफ है और मनुष्य शक्ति का निर्माण दूसरी तरफ है। यह शुक्र है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में Skill Development का एक कार्यक्रम चल रहा है। मेरे pertinent questions दो ही हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः एक पूछिए।

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धेः एक प्रश्न यह है कि Industry-Institute interaction जो है, जब तक वह नहीं बढ़ेगा, तब तक हम उद्योग जगत की आवश्यकता और जो मनुष्य शक्ति का निर्माण है, उसमें आवश्यक तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। क्या इसकी कोई योजना है?

दूसरा, जो पाठ्यक्रम है, क्या उसका कोई biennial review हो सकता है, क्योंकि तकनीक और शोध इतनी गति से आगे बढ़ रहे हैं कि उस रूप में हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हो रहा है? मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि curriculum समयानुकूल revise होना चाहिए और वह dynamic है। उच्च शिक्षा के स्तर के बारे में बहुत सारे initiatives लिए गए हैं, जब इसके ऊपर अलग से चर्चा होगी, तो हम इसके बारे में डिटेल में बताएँगे। हमारे यहां National Employment Enhancement Mission नामक एक योजना चल रही है। इसके अन्दर skilling के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और इसके द्वारा बहुत सारा उपक्रम किया जा रहा है। IIITs are funded by AICTE. CII-AICTE के बारे में आपने जो industrial interaction की बात की, वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए industry की रिसर्च की जो customized requirements हैं, उनके लिए भी एक योजना तैयार हो रही है। Industry interaction से courses के relevance पर ध्यान दिया जा रहा है। ITIs बहुत मात्रा में अभी industry चला भी रही हैं, successful हैं और सबको तुरंत रोजगार मिल रहा है। Industry interaction के बारे में जैसा दुनिया का अनुभव है, वैसे ही यहां भी academia और industry interaction बिल्कुल चलना चाहिए, तभी शिक्षा सार्थक

होगी। Colleges are required to have industrial tie-up for practical apprenticeship. इन तीनों-चारों मुकामों पर काम चल रहा है and this is a very important step which we want to take it forward.

Women and children affected by nutrition deficiency

*49. SHRIMATI RAJANI PATIL: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether as per various news reports there are large number of women and children affected by nutrition deficiency in various parts of the country;

(b) if so, the action taken by Government to meet this challenge;

(c) the details of funds released for different women and child development schemes during the last two years, State/UT-wise; and

(d) whether Government has formulated any schemes to improve the situation and to get rid of this problem in the country and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Nutrition deficiency is one of the causes under-nutrition amongst women and children. The level of under-nutrition, wasting and stunting is measured through periodical surveys conducted by National Family Health Survey (NFHS) of Ministry of Health and Family Welfare, etc.

According to National Family Health Survey (NFHS-3) (2005-06) carried out by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, 42.5% children under 5 years of age are underweight, 48% are stunted, 19.8% are wasted and 69.5 % of under-five children are anaemic. Among women in the age group of 15-49 years, 35.6% have BMI less than 18.5 and 55.3% are anaemic in the country.

However, as per the Rapid Survey on Children (RSoC), 2013-14, commissioned by Ministry of Women and Child Development, there is a reduction in underweight among children under 5 years of age from 42.5% in NFHS-3 to 29.4%, stunting from 48% in NFHS-3 to 38.7% and wasting from 19.8% in NFHS-3 to 15.1% in RSoC.

(b) to (d) Malnutrition is complex, multi-dimensional and inter-generational in nature, needing convergence of interventions, coordination and concerted action from various sectors. The Government has accorded high priority to the issue of malnutrition